

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13968/2024

मैसर्स लक्ष्मीप्रकाश गारमेंट्स प्रा. लिमिटेड, इसका पंजीकृत कार्यालय ई-195 (ए) रीको औद्योगिक क्षेत्र, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान, 302020 में इसके निदेशक श्री प्रकाश चंद मंघरानी पुत्र स्वर्गीय श्री मूल चंद मंघरानी, उम्र-65 के माध्यम से है।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. बजरंग सिंह राठौड़ पुत्र भंवर सिंह राठौड़, निवासी 80, बजरंग विहार, गोपालपुरा रेलवे ब्रिज के पास, जयपुर।
2. मैसर्स ऑटोपाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 1, नारानिया कंपाउंड वॉल फेज III, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सीतापुरा, जयपुर राजस्थान-302022 है।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री प्रथ पारीक,
श्री वैभव शर्मा
प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री धर्मेन्द्र जैन,
श्री अरविंद कुमार अरोड़ा और
सुश्री तनुश्री कुमावत के साथ

जस्टिस अनूप कुमार ढांड

आरक्षित तिथि : 10/09/2024
उच्चारण तिथि : 21/09/2024
प्रकाशनीय

आदेश

व्याख्या की सुविधा के लिए, इस निर्णय को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है:

सूची

- (1) रिट याचिका का विवरण2
- (2) तथ्यात्मक मैट्रिक्स और प्रस्तुतियाँ2
- (3) विश्लेषण5
- (4) संदर्भित निर्णय7
- (5) अवलोकन20
- (6) निष्कर्ष21
- (7) अतिरिक्त निर्देश21

रिट याचिका का विवरणः

1. इस रिट याचिका के माध्यम से, श्रम न्यायालय-I, जयपुर द्वारा एलसीसी प्रकरण संख्या 01/2000 में पारित दिनांक 29.05.2024 के आक्षेपित आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा प्रतिवादी-कर्मचारी द्वारा सीपीसी के आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत याचिकाकर्ता को पक्षकार बनाने के लिए दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है।

तथ्यात्मक मैट्रिक्स और प्रस्तुतियाँः

2. सर्वप्रथम, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता-कंपनी का मेसर्स ऑटोपाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (संक्षेप में "प्रतिवादी-कंपनी") से कोई संबंध नहीं है। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उक्त कंपनी और प्रतिवादी-कर्मचारी के बीच एक औद्योगिक विवाद लंबित है। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी-कंपनी मेसर्स ऑटोपाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा याचिकाकर्ता-कंपनी को दिनांक 10.10.2019 के पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से भूमि का एक टुकड़ा बेचा गया था। वकील ने कहा कि केवल उक्त बिक्री विलेख के आधार पर याचिकाकर्ता-कंपनी को प्रतिवादी-कर्मचारी और प्रतिवादी कंपनी मेसर्स ऑटोपाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच लंबित मुकदमे में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है। वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता का मेसर्स ऑटोपाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अधिकारों और दायित्वों से कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि उसने केवल जमीन का एक टुकड़ा खरीदा है और उस आधार पर मेसर्स ऑटोपाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कोई दायित्व याचिकाकर्ता पर नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए, इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता श्रम न्यायालय के समक्ष लंबित मामले में न तो आवश्यक और न ही उचित पक्ष है। वकील ने कहा कि यह आपत्ति याचिकाकर्ता द्वारा श्रम न्यायालय के समक्ष उठाई गई थी, लेकिन श्रम न्यायालय ने मेसर्स अराफात पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम मेसर्स जे.के. स्टाफ एसोसिएशन, कोटा और अन्य के मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित फैसले की गलत व्याख्या करके। (एसबी सिविल रिट याचिका संख्या **12663/2018**) दिनांक 08.08.2019, जिसमें इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने माना है कि याचिकाकर्ता एक आवश्यक पक्ष है और तदनुसार याचिकाकर्ता को पक्षकार बनाया गया है। वकील ने प्रस्तुत किया कि मेसर्स अराफात पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होता है, क्योंकि उपरोक्त मामले में मेसर्स अराफात पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स जे.के. स्टाफ

एसोसिएशन के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, लेकिन वर्तमान मामले में प्रतिवादियों के बीच ऐसा कोई त्रिपक्षीय समझौता नहीं हुआ है और याचिकाकर्ता-कंपनी प्रतिवादी-कर्मचारी और प्रतिवादी-कंपनी मेसर्स ऑटोपाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ सभी प्रकार की देनदारियों और भार से मुक्त है। वकील ने प्रस्तुत किया कि इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक है और दिनांक 29.05.2024 का आरोपित आदेश रद्द करने और रद्द करने योग्य है।

3. इसके विपरीत, प्रतिवादी कामगार के विद्वान वकील ने याचिकाकर्ता-कंपनी के वकील द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी-कामगार की सेवाओं को पूर्ववर्ती प्रतिवादी-कंपनी यानी मेसर्स ऑटोपाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा अवैध रूप से समाप्त कर दिया गया था और श्रम न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी-कंपनी मेसर्स ऑटोपाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ कामगारों के 40 से अधिक मुकदमे लंबित हैं। वकील ने प्रस्तुत किया कि अपनी देयता से बचने के लिए, प्रतिवादी-कंपनी मेसर्स ऑटोपाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा संपत्ति का कुछ हिस्सा 10.10.2019 को पंजीकृत बिक्री विलेख निष्पादित करके याचिकाकर्ता-कंपनी को बेच दिया गया था। वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता से प्रतिफल राशि प्राप्त करने के बाद, पूर्ववर्ती नियोक्ता यानी मेसर्स ऑटोपाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (प्रतिवादी-कंपनी) ने इसे "दिवालिया" घोषित करने के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (संक्षेप में "एनसीएलटी") का दरवाजा खटखटाया। वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी-कंपनी की उपरोक्त कार्रवाई इसे धारा 206 भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में "आईपीसी") के तहत अपराध के लिए उत्तरदायी बनाती है। वकील ने प्रस्तुत किया कि यदि श्रम न्यायालय द्वारा कर्मचारी के पक्ष में कोई पुरस्कार पारित किया जाता है, तो निश्चित रूप से याचिकाकर्ता-कंपनी भी उसका पालन करने की हकदार होगी, इसलिए, इन परिस्थितियों में, श्रम न्यायालय ने कर्मचारी द्वारा उसके और प्रतिवादी-कंपनी मेसर्स ऑटोपाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच लंबित मुकदमे में याचिकाकर्ता-कंपनी को पक्षकार बनाने के लिए दायर आवेदन को अनुमति देने में कोई त्रुटि नहीं की है। अपने तर्कों के समर्थन में, उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा एम.एन. करियप्पा बनाम श्रीमती रोसम्मा एवं अन्य, **2013 (138) एफएलआर 247** मामले में पारित निर्णय का हवाला दिया है। वकील ने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त प्रस्तुतियों के मद्देनजर, याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

विश्लेषणः

4. बार में प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरणों को सुना और उन पर विचार किया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।
5. याचिकाकर्ता-कंपनी के वकील के तर्क का सार यह है कि याचिकाकर्ता-कंपनी प्रतिवादी-कंपनी की हित-उत्तराधिकारी नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता-कंपनी ने प्रतिवादी-कंपनी से केवल भूमि का एक टुकड़ा खरीदा है और उसने संपत्ति को चालू व्यवसाय के रूप में नहीं खरीदा है। यह भी तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी-कंपनी का व्यवसाय न तो याचिकाकर्ता-कंपनी द्वारा लिया गया है और न ही उसमें विलय किया गया है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के बीच लंबित मुकदमे में याचिकाकर्ता-कंपनी न तो आवश्यक है और न ही उचित पक्षकार है।
6. याचिकाकर्ता-कंपनी और प्रतिवादी-कर्मचारी दोनों के वकीलों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में "1947 का अधिनियम") की धारा 18 का हवाला दिया है, और उसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"18. वे व्यक्ति जिन पर समझौते और पंचाट बाध्यकारी हैं

(1) नियोक्ता और कर्मकार के बीच सुलह कार्यवाही के अलावा किसी अन्य तरीके से किया गया समझौता समझौते के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(2) उप-धारा (3) के प्रावधानों के अधीन, एक मध्यस्थता पंचाट जो प्रवर्तनीय हो गया है, समझौते के उन पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा जिन्होंने विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा था।

(3) इस अधिनियम के तहत सुलह कार्यवाही या किसी मामले में मध्यस्थता पुरस्कार जहां धारा 10-ए की उपधारा (3ए) के तहत अधिसूचना जारी की गई है] या [श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का पुरस्कार] जो लागू हो गया है, बाध्यकारी होगा

(क) औद्योगिक विवाद के सभी पक्ष;

(ख) विवाद के पक्षकार के रूप में कार्यवाही में उपस्थित होने के लिए समन किए गए अन्य सभी पक्ष, जब तक कि बोर्ड, [मध्यस्थ,] [श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण], जैसा भी मामला हो, यह राय दर्ज न कर दे कि उन्हें उचित कारण के बिना समन किया गया था;

(ग) जहाँ खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट पक्ष, उस प्रतिष्ठान के संबंध में नियोक्ता, उसके उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी या समनुदेशिनी है जिससे विवाद संबंधित है;

घ) जहाँ खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट पक्ष, कामगारों से बना है, वे सभी व्यक्ति जो उस प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठान के भाग में, जैसा भी मामला हो, नियोजित थे, जिससे विवाद संबंधित है, विवाद की तिथि पर और वे सभी व्यक्ति जो बाद में उस प्रतिष्ठान या उसके भाग में नियोजित हो गए।”

1947 के अधिनियम की धारा 18(3)(सी) के अवलोकन से मुख्य शब्द "विवाद से संबंधित प्रतिष्ठान के संबंध में उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी या समनुदेशिनी" इंगित होते हैं। वर्तमान मामले में, प्रतिवादी-कंपनी का व्यवसाय उसी द्वारा चलाया जाता था और वर्ष 2000 से श्रम न्यायालय में प्रतिवादी-कर्मचारी और प्रतिवादी कंपनी के बीच औद्योगिक विवाद के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी-कंपनी ने 10.10.2019 को एक पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा अपनी भूमि के कुछ हिस्से याचिकाकर्ता-कंपनी को बेच दिए।

7. इस अनुवर्ती घटना के कारण, श्रम न्यायालय ने याचिकाकर्ता-कंपनी को उक्त कार्यवाही में पक्षकार बनाया है। अब, इस न्यायालय के विचारणीय प्रश्न यह है कि "क्या याचिकाकर्ता कंपनी को पक्षकार बनाया जा सकता है या नहीं?"

8. सिविल प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'सीपीसी') के आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत निहित प्रावधान, कार्यवाही के किसी भी चरण में, किसी भी पक्षकार को जोड़ने की न्यायालय की शक्ति से संबंधित हैं, यदि न्यायालय के समक्ष उपस्थित व्यक्ति मामले में शामिल मुद्दे के प्रभावी न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक या उचित है।

इस याचिका में शामिल मुद्दे पर संदर्भित निर्णय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों के विचारः

9. श्री कांची कामकोटि पीठम चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल बनाम औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं अन्य, **2003** एससीसी ऑनलाइन मैड **643** में प्रकाशित मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने यह माना है कि औद्योगिक विवाद में पक्षकारों को पक्षकार बनाने या जोड़ने की श्रम न्यायालय की शक्ति पूरी तरह से निषिद्ध नहीं है। विवाद के पूर्ण निर्णय के उद्देश्य से, औद्योगिक न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय के पास नियोक्ता, कर्मचारी या अन्य व्यक्तियों के अलावा अन्य पक्षों को सुलह अधिकारी के समक्ष पक्षकार बनाने या जोड़ने की

शक्ति सहित आकस्मिक शक्तियाँ हैं। अपने-अपने दावे को प्रमाणित करना पक्षों का कार्य है और अंततः न्यायाधिकरण का यह कर्तव्य है कि वह मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के संदर्भ में उन पर विचार करे और एक न्यायसंगत निर्णय पर पहुँचे। निर्णय का प्रासंगिक अंश निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत है:

“13. यह भी ध्यान रखना प्रासंगिक है कि केंद्रीय नियम, 1957 का नियम 24 श्रम न्यायालयों को अधिकार प्रदान करता है, जो सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत सिविल न्यायालय में खोज और निरीक्षण, स्थगन देने, हलफनामे पर लिए गए साक्ष्य को स्वीकार करने, किसी भी व्यक्ति को बुलाने और उसकी जांच करने के संबंध में निहित हैं, जिसका साक्ष्य सामग्री प्रतीत होता है। ऊपर उल्लिखित प्रावधानों और उठाए गए विवाद के संयुक्त पढ़ने से, मेरा विचार है कि श्रम न्यायालय / औद्योगिक न्यायाधिकरण को नियोक्ता और कर्मचारी के अलावा अन्य व्यक्तियों को निर्देश देने से बाहर नहीं रखा गया है, जिनकी आवश्यकता मुद्दे के पूर्ण न्यायनिर्णयन के लिए होगी। औद्योगिक विवाद अधिनियम के Ss. 2 (k), 10, 11 और 18 के साथ-साथ नियमों के प्रावधानों को पढ़ने से पता चलता है कि परीक्षण हमेशा होना चाहिए, न्यायनिर्णयन को प्रभावी और लागू करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक पक्ष को जोड़ना। पूर्णतः निषिद्ध। यदि श्रम न्यायालय का विचार है कि पंचाट के प्रवर्तन के लिए ऐसे पक्षकार की उपस्थिति आवश्यक है, तो उसके पास औद्योगिक विवाद में किसी पक्षकार को जोड़ने या शामिल करने की पर्याप्त शक्ति है। प्राधिकारी, विवाद के अतिरिक्त, संदर्भ आदेश में विवाद से संबंधित किसी भी मामले को निर्दिष्ट कर सकता है।

14. इस संबंध में, पलानीसामी आर. बनाम पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, [2001 (3) एल.एल.एन. 638] मामले का संदर्भ देना प्रासंगिक है। इसी तरह के मुद्दे पर विचार करते हुए, न्यायमूर्ति के. रविराज पांडियन ने अनुच्छेद 12, पृष्ठ 641 में निष्कर्ष निकाला है कि:

“... श्रम न्यायालय द्वारा किसी पक्ष को जोड़ने या पक्षकार बनाने की शक्ति पूर्णतः निषिद्ध नहीं है। यदि श्रम न्यायालय की राय है कि प्रभावी और प्रवर्तनीय न्यायनिर्णयन के लिए पक्षकार की उपस्थिति आवश्यक है, तो वह किसी पक्ष को जोड़ सकता है। इसके अतिरिक्त, श्रम न्यायालय उन मामलों पर भी न्यायनिर्णयन कर सकता है, जो संदर्भ आदेश से संबंधित हैं।”

15. नटराजन बनाम पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, [2001 (1) एल.एल.एन. 539] के मामले का उल्लेख करना भी उचित है, जिसमें एफ.एम. इब्राहिम कलीफुल्ला, जे. ने समान परिस्थिति में यह माना है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 18-बी के तहत श्रम न्यायालय में उन व्यक्तियों को

भी पक्षकार बनाने की शक्तियां निहित हैं, जिन्हें सुलह अधिकारी के समक्ष पक्षकार नहीं बनाया गया है, उसके समक्ष विवाद के पक्षकार के रूप में। चूंकि दोनों निर्णय वैधानिक प्रावधानों के अनुसार हैं और संबंधित पक्षों के हितों पर विचार किया गया है, इसलिए मैं इससे सहमत हूं। ऊपर संदर्भित वैधानिक प्रावधानों के प्रकाश में और पूर्ण न्यायनिर्णयन के उद्देश्य से, मेरा विचार है कि औद्योगिक न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय के पास नियोक्ता, कर्मचारी या सुलह अधिकारी के समक्ष व्यक्तियों के अलावा अन्य पक्षों को पक्षकार बनाने या जोड़ने सहित आकस्मिक शक्तियां हैं।

16. यह भी ध्यान देने योग्य है कि सभी वित्तीय संस्थानों ने तमिलनाडु अस्पताल की संपत्ति रिट-याचिकाकर्ता को बेच दी है और याचिकाकर्ता का न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित एक औद्योगिक विवाद में हित है। मैं न्यायाधिकरण के इस निष्कर्ष से सहमत हूँ कि रिट-याचिकाकर्ता एक आवश्यक पक्ष है जो औद्योगिक विवाद से संबंधित प्रश्न पर तथ्यात्मक और पूर्ण रूप से निर्णय लेने में सक्षम है। यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता को औद्योगिक विवाद में एक पक्ष के रूप में शामिल किया गया है, यह स्वतः ही नहीं मान लिया जाना चाहिए कि दायित्व उस पर आरोपित किया जाना है। पक्षकारों को अपने-अपने दावे को प्रमाणित करना है और अंततः न्यायाधिकरण का यह कर्तव्य है कि वह मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के संदर्भ में उन पर विचार करे और एक न्यायोचित निर्णय पर पहुँचे। जब ऐसा उपाय उपलब्ध है, तो मैं याचिकाकर्ता द्वारा अपनाए गए रुख को समझने में असमर्थ हूँ। दायित्व सहित सभी प्रश्न/आपत्तियाँ खुली रखी जाती हैं और न्यायाधिकरण को मुख्य औद्योगिक विवाद का निर्णय करते समय विचार करके आदेश पारित करना है। उपरोक्त अवलोकन के साथ, यह रिट याचिका खारिज की जाती है। कोई खर्च नहीं। परिणामस्वरूप, संबंधित डब्ल्यू.पी.एम.पी. और डब्ल्यू.वी.एम.पी. को भी बर्खास्त किया जाता है।”

10. यहाँ विचारणीय मुख्य परीक्षण यह है कि क्या किसी पक्षकार का शामिल न होना कार्यवाही को अप्रभावी या अप्रवर्तनीय बना देगा। इस परीक्षण के आलोक में, किसी पक्षकार को पक्षकार बनाने की श्रम न्यायालय की शक्ति को सीमित माना जाना चाहिए। किसी औद्योगिक विवाद के अंतिम निर्णय के दौरान, श्रम न्यायालय को इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि क्या पक्षकार को बिना किसी वैध कारण या उचित कारण के बुलाया गया है। हालाँकि, यदि विवाद के उचित निर्णय के लिए किसी अतिरिक्त पक्षकार को पक्षकार बनाना आवश्यक है, तो श्रम न्यायालय मामले के दायरे का विस्तार करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता है। अंततः, प्रत्येक निर्णय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ग्रेट इंडियन मोटर वर्क्स लिमिटेड, एवं अन्य बनाम कर्मचारी एवं अन्य के मामले में, जो **1959** एससीसी ऑनलाइन एससी **154** में रिपोर्ट किया गया था, इसी मुद्दे पर यह माना है कि केवल संदर्भ का वह पक्ष जो निर्णय से व्यथित हो, अपील का पक्षकार हो सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के आदेश की पुष्टि करते हुए, जहां तक नीलामी क्रेता का संबंध है, संदर्भ को अक्षम घोषित किया, जिसके तहत तीन मुख्य आधारों पर चर्चा की गई कि क्या नीलामी-क्रेता को विवाद में पक्ष बनाया जा सकता है, और निर्णय का प्रासंगिक उद्धरण निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"9. अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया है कि औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) अधिनियम (1950 का 48) (जिसे 1956 के अधिनियम 36 द्वारा निरस्त कर दिया गया था) की धारा 12, धारा 3 के साथ पठित, के प्रावधानों के मद्देनजर, जो अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील करने को नियंत्रित करते थे, उस न्यायाधिकरण में की गई अपील सक्षम थी, और उस पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई और निर्णय किया जाना चाहिए था। धारा 3 और 12 के प्रावधान, जिनकी हमें इस मामले में व्याख्या करनी है, इस प्रकार हैं:

"3. इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी ऐसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

"12. इस अधिनियम के अधीन किसी औद्योगिक न्यायाधिकरण के किसी अधिनिर्णय या निर्णय के विरुद्ध अपील अपीलीय न्यायाधिकरण में निम्नलिखित द्वारा प्रस्तुत की जा सकेगी—

(i) कोई भी पक्ष जो पंचाट या निर्णय से व्यथित है; या (ii) समुचित सरकार या केन्द्र सरकार, जहां वह समुचित सरकार नहीं है, चाहे ऐसी सरकार विवाद में पक्षकार हो या नहीं।" हमें सबसे पहले यह निर्धारित करना है कि क्या भारतीय कंपनी अधिनियम में, भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 की धारा 179 (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 457 के रूप में पुनः अधिनियमित) के विशेष संदर्भ में, कुछ ऐसा है जो औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) अधिनियम, 1950 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जाएगा) के प्रावधानों से असंगत है। यदि कंपनी अधिनियम के उन प्रावधानों में कुछ भी अधिनियम के प्रावधानों से असंगत है, तो अधिनियम के प्रावधान ही मान्य होंगे। इसलिए, हमें

धारा 12 के प्रावधानों की व्याख्या करनी होगी जो विशेष रूप से अपीलों से संबंधित हैं। वह धारा किसी भी पक्ष द्वारा अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति देती है जो पुरस्कार से व्यथित है (हमारे वर्तमान उद्देश्य के लिए आवश्यक नहीं शब्दों को छोड़कर)। यह अपील के लिए सामान्य वैधानिक प्रावधान है, जो अन्यथा लागू नहीं होता। यह स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से यह नहीं कहता है कि कंपनी अधिनियम के वे विशिष्ट प्रावधान निरस्त या संशोधित किए गए हैं। जहाँ तक परिसमापक का संबंध है, न्यायालय की अपेक्षित स्वीकृति की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। भारतीय कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत, परिसमापनाधीन कंपनी के मामलों का प्रभार आधिकारिक परिसमापक के पास होता है, और धारा 457 के तहत, केवल परिसमापक ही न्यायालय की स्वीकृति से कंपनी के नाम और उसकी ओर से कोई भी वाद या अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए अधिकृत होता है। इस प्रकार, अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों और कंपनी अधिनियम के बीच कोई असंगति नहीं है, जिसमें केवल समापन प्रक्रिया में किसी कंपनी के परिसमापक द्वारा अपील दायर करने के लिए एक पूर्व शर्त निर्धारित की गई है। यह एक अत्यंत विशेष मामले से संबंधित है और अपील के सामान्य अधिकार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चूँकि, वर्तमान मामले में, न्यायालय ने परिसमापकों को अपील दायर करने के लिए आवश्यक स्वीकृति देने से इनकार कर दिया था, इसलिए कंपनी की ओर से कोई अपील दायर नहीं की जा सकती थी। इसलिए, जहाँ तक अपील का तात्पर्य पूर्वोक्त प्रबंध निदेशक के माध्यम से कंपनी की ओर से किया जाना था, वह पूरी तरह से अक्षम थी। लेकिन अपील न केवल कंपनी द्वारा, बल्कि उक्त के.डी. नंदी द्वारा कंपनी के लेनदार, अंशदायी या नीलामी-क्रेता के रूप में भी किया गया था। जहाँ तक अपील के इस भाग का संबंध है, यह स्पष्ट है कि केवल संदर्भ का वह पक्ष जो निर्णय से व्यथित हो, अपील का पक्षकार हो सकता है। के.डी. नंदी लेनदार या अंशदायी के रूप में पक्षकार नहीं थे। जैसा कि पहले ही संकेत दिया जा चुका है, उन्हें कंपनी के व्यवसाय के नीलामी क्रेता की हैसियत से संदर्भ के पक्षकार के रूप में शामिल किया गया था। जहाँ तक उस हैसियत का संबंध है, न्यायाधिकरण के आदेश से यह स्पष्ट है कि उनके विरुद्ध इस रूप में कोई निर्णय नहीं दिया गया था। इसलिए, उन्हें निर्णय से व्यथित पक्षकार नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि उन्हें इसकी शर्तों से मुक्त कर दिया गया था। न्यायाधिकरण ने इसे तीन मुख्य आधारों पर रखा- (1) कि नीलामी-क्रेता ने कंपनी के व्यवसाय को सभी भारों, व्ययों और देनदारियों से मुक्त खरीदा था, (2) कि व्यवसाय का कब्जा

नीलामी-क्रेता को सौंपे जाने से पहले परिसमापकों द्वारा, और (3) नीलामी क्रेता और जिन श्रमिकों की सेवाएं इस प्रकार समाप्त की गई थीं, उनके बीच नियोक्ता और कर्मचारियों का कोई संबंध नहीं था। न्यायाधिकरण ने, मामले के इस दृष्टिकोण से, जहां तक नीलामी-क्रेता का संबंध था, संदर्भ को अक्षम घोषित किया। यह आदेश, न्यायाधिकरण ने स्वयं नीलामी-क्रेता के कहने पर पारित किया। इसलिए, नीलामी-क्रेता उस आदेश को प्राप्त करने में सफल रहा जिसे न्यायाधिकरण ने पारित किया, यह मानते हुए कि जहां तक उसका संबंध था, संदर्भ अक्षम था। इन तथ्यों के मद्देनजर, यह माना जाना चाहिए कि जहां तक नीलामी-क्रेता का संबंध है, वह औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए पुरस्कार से व्यथित नहीं था। ऐसा होने पर, अधिनियम की धारा 12 के प्रावधान, नीलामी-क्रेता द्वारा दायर की गई कथित अपील पर लागू नहीं होते हैं। यह समझना थोड़ा मुश्किल है कि नीलामी-क्रेता, ऊपर दिए गए आदेश को अपने पक्ष में प्राप्त करने में सफल होने के बाद, उन्होंने अपना विचार बदल दिया और अपील दायर की, जो कि घटित घटनाओं के आधार पर स्वीकार्य नहीं थी।

12. इसी तरह का मुद्दा एआईआर **1963** एससी **1489** में रिपोर्ट किए गए अंकापल्ले को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी लिमिटेड बनाम वर्कमैन और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष आया था और इसे पैरा 9 और 10 में निम्नानुसार माना गया है:

“9. यह प्रश्न कि क्या किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के क्रेता को विक्रेता का हित-उत्तराधिकारी माना जा सकता है, कई प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करके तय किया जाना चाहिए। क्या क्रेता ने पूरा व्यवसाय खरीदा था? क्या विक्री लेनदेन के समय खरीदा गया व्यवसाय एक चालू प्रतिष्ठान था? क्या खरीदा गया व्यवसाय पहले की तरह उसी स्थान पर चलाया जा रहा है? क्या व्यवसाय समय में पर्याप्त रुकावट के बिना चलाया जा रहा है? क्या खरीदा गया व्यवसाय विक्रेता के हाथों में व्यवसाय के समान या उसी तरह चलाया जा रहा है? यदि व्यवसाय की निरंतरता में रुकावट आई है, तो रुकावट की प्रकृति क्या है और इसके लिए कौन से कारण जिम्मेदार थे? रुकावट की अवधि क्या है? क्या ख्याति खरीदी गई है? क्या केवल कुछ भागों की खरीद की गई है और क्रेता ने उक्त भागों को खरीदने के बाद कुछ अन्य नए भाग खरीदे हैं और अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया है जो पुराने व्यवसाय के समान नहीं है, लेकिन उसके समान है? इन और अन्य सभी प्रासंगिक कारकों को इस प्रश्न का निर्णय करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या क्रेता को विक्रेता का हित-

उत्तराधिकारी कहा जा सकता है। औद्योगिक न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ विक्रेता। इस संबंध में इस बात पर ज़ोर देना शायद ही आवश्यक है कि यद्यपि उदाहरण के तौर पर हमने जिन सभी तथ्यों का उल्लेख किया है, वे प्रासंगिक हैं, फिर भी इनमें से किसी एक तथ्य के महत्व को बढ़ा-चढ़ाकर बताना या यह अटल नियम अपनाना अनुचित होगा कि उनमें से किसी एक की उपस्थिति या अनुपस्थिति ही मामले को किसी न किसी रूप में निर्णायक बनाती है। यदि औद्योगिक न्यायनिर्णयन इस बात पर ज़ोर देता है कि क्रेता को विक्रेता प्रतिष्ठान की संपूर्ण संपत्ति खरीदनी होगी, तभी उसे हित-उत्तराधिकारी माना जा सकता है, तो यह बहुत संभव है कि संपत्ति का एक नगण्य भाग ही हस्तांतरण का विषय न हो और यह तर्क दिया जा सकता है कि उक्त अंश को बहिष्कृत करने से औद्योगिक न्यायनिर्णयन क्रेता को हित-उत्तराधिकारी मानने से वंचित हो जाता है। हालाँकि, इस तर्क पर इस साधारण कारण से विचार नहीं किया जा सकता कि इस प्रश्न का निर्णय करते समय औद्योगिक न्यायनिर्णयन मामले के सार को देखेगा और केवल हस्तांतरण के स्वरूप से निर्देशित नहीं होगा। विक्रेता प्रतिष्ठान की संपूर्ण संपत्ति के बारे में हमने जो कहा है, वह इस पर भी लागू होगा। सद्भावना, जो किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान की एक अमूर्त संपत्ति है। यदि सद्भावना, शेष मूर्त संपत्ति के साथ बेची गई है, तो यह इस तर्क का दृढ़ता से समर्थन करेगी कि क्रेता हित-उत्तराधिकारी है; लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि यदि सद्भावना नहीं बेची गई है, तो केवल यही अनिवार्य रूप से यह दर्शाएगा कि हस्तांतरिणी हित-उत्तराधिकारी नहीं है। इस प्रश्न का निर्णय अंततः सभी प्रासंगिक कारकों के मूल्यांकन पर निर्भर होना चाहिए और उनमें से किसी एक को सर्वोपरि या निर्णायक महत्व मानकर इस पर निर्णय नहीं लिया जा सकता।

10. इस कानूनी स्थिति के आलोक में ही विक्रेता कंपनी के संबंध में अपीलकर्ता के चरित्र के प्रश्न का निर्णय किया जाना है। यह स्मरणीय है कि विक्रेता कंपनी ने अपीलकर्ता को प्रतिष्ठान इसलिए बेचा क्योंकि उसे आवर्ती घाटे की समस्या का सामना करना पड़ रहा था, और इसलिए, अपीलकर्ता, प्रतिष्ठान खरीदते समय, बिक्री लेनदेन में अग्रिम और बकाया दोनों को शामिल करने के लिए तैयार नहीं था। अपीलकर्ता समिति का गठन स्थानीय गन्ना उत्पादकों द्वारा चीनी के निर्माण के उद्देश्य से किया गया है जो दोनों के लिए उपयुक्त हो। उनमें से एक बारी-बारी से और इसलिए, क्रेता विशेष रूप से बिक्री लेनदेन में कंपनी की सद्भावना को शामिल करने में दिलचस्पी नहीं रखता था। प्रसंस्कृत चीनी के 4,000 बैगों को बाहर रखने से पता चलता है कि क्रेता उस मामले में कंपनी को समायोजित करना चाहता था। दूसरी ओर, अपीलकर्ता ने बिना किसी सराहनीय ब्रेक के कंपनी का व्यवसाय चलाया है; इस प्रकार किया गया व्यवसाय कंपनी के समान है, व्यवसाय का स्थान समान है, और बिक्री लेनदेन में प्रवेश करने का मूल उद्देश्य स्थानीय गन्ना उत्पादकों को कंपनी का व्यवसाय

चलाने में सक्षम बनाना था। इसलिए, हम यह दृष्टिकोण लेने के लिए इच्छुक हैं कि इस मामले में सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कानूनी रूप से सही था कि अपीलकर्ता कंपनी का उत्तराधिकारी है।

13. उपरोक्त निर्णय का अनुसरण कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एम.एन. करियप्पा बनाम श्रीमती रोसम्मा एवं अन्य के मामले में **2013 (138) एफएलआर 247** में किया था और पैरा 19 से 21 में निम्नानुसार निर्णय दिया गया है:

“19. हमारे विचार में, उक्त कथन अनकपल्ला को-ऑप एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों के विपरीत है। यह आवश्यक नहीं है कि बिक्री लेनदेन के समय व्यवसाय को एक चालू व्यवसाय के रूप में खरीदा जाए। मौजूदा व्यवसाय के कुछ हिस्सों को कुछ अन्य हिस्सों या संपत्तियों की खरीद करके एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए खरीदा जा सकता है। फिर भी, हस्तांतरिती अधिनियम की धारा 18 के अर्थ में हित-उत्तराधिकारी बन जाएगा। यदि पुराने प्रतिष्ठान के विक्रेता से खरीदी गई संपत्तियों से एक नया व्यवसाय शुरू भी किया जाता है, तब भी हस्तांतरिती को अधिनियम की धारा 18 के प्रयोजन के लिए हित-उत्तराधिकारी माना जाएगा, जब तक कि यह इस तथ्य से अलग न हो कि औद्योगिक विवाद उस प्रतिष्ठान से संबंधित था जिसे मूल स्वामी या नियोक्ता द्वारा हस्तांतरित या सौंपा गया था। इस प्रकार, व्यवसाय को एक चालू व्यवसाय के रूप में हस्तांतरित करना, उस प्रतिष्ठान के संबंध में हित-उत्तराधिकारी के रूप में हस्तांतरिती को मानने के लिए अनिवार्य शर्त नहीं है जिससे विवाद संबंधित है। इसलिए, हम इस फैसले को खारिज करते हैं। पीएसआई डाटा सिस्टम्स लिमिटेड में विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय का अनुपात।

20. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता ने कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान संपत्ति खरीदी थी, जो खरीदा गया है वह एक कॉफी एस्टेट प्रतिष्ठान है। भले ही कॉफी एस्टेट को एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में नहीं खरीदा गया हो, कॉफी एस्टेट खरीदे जाने का तात्पर्य यह होगा कि अपीलकर्ता उस प्रतिष्ठान के संबंध में हित-उत्तराधिकारी है जिससे विवाद संबंधित है और उसके कानूनी प्रतिनिधि पंचाट से बंधे हैं। इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश का यह मानना सही था कि पी.एस.आई. डाटा सिस्टम्स लिमिटेड का वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

21. विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह माना है कि श्रम न्यायालय द्वारा संपत्ति के मालिक पर दायित्व थोपना उचित था और यदि संपत्ति का वर्तमान मालिक श्रम न्यायालय के पंचाट से संतुष्ट है, तो बिक्री विलेख में संबंधित खंड के आधार पर, वर्तमान मालिक अर्थात् अपीलकर्ता क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है,

लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 और 2 - कामगारों को पंचाट के फल से वंचित नहीं किया जा सकता है। विद्वान एकल न्यायाधीश के उक्त निर्देशों और टिप्पणियों में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। विक्रय विलेख के आधार पर, अपीलकर्ता प्रतिवादी संख्या 3 से 8 तक से, विधि अनुसार, पंचाट के तहत जमा की गई राशि की वसूली की मांग करने के लिए स्वतंत्र हैं। चूंकि हमें इस अपील में कोई दम नहीं दिखता, इसलिए इसे खारिज किया जाता है। पक्षकार अपने-अपने खर्चे स्वयं वहन करेंगे।

14. इसी प्रकार मेसर्स अराफात पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में भी इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने निर्णय के पैरा 21 में इसी प्रकार के मुद्दे पर विचार किया है:

“21. पक्षों के वकील को सुनने और मामले के रिकॉर्ड के साथ-साथ पक्षों के वकील द्वारा उद्धृत मिसाल कानून का अवलोकन करने के बाद, यह न्यायालय इस राय का है कि 1947 के अधिनियम की धारा 18 अपने आप में श्रम न्यायालय को किसी भी पक्ष को नियोक्ता के रूप में पक्षकार बनाने की शक्ति का स्पष्ट विधायी आशय रखती है, जिसमें उस प्रतिष्ठान के संबंध में उसके उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे जिससे विवाद संबंधित है। वर्तमान मामले में, यह विवादित नहीं है कि विचाराधीन प्रतिष्ठान वह है जो प्रश्नगत संदर्भ द्वारा न्यायनिर्णित विवाद से संबंधित है। संदर्भ का दायरा प्रश्नगत प्रतिष्ठान से उत्पन्न कार्य के अधिकार हैं, जो प्रतिवादी कंपनी के पास था और अब त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार वर्तमान याचिकाकर्ता को दे दिया गया है। त्रिपक्षीय समझौता बहुत व्यापक है और इसमें कामगारों के लगभग सभी अधिकार शामिल हैं, लेकिन फिर भी, अगर कोई प्रतिबंध है, जो त्रिपक्षीय समझौते में है, तो इसे अधिनियम की धारा 18(3)(सी) की भावना के विपरीत नहीं पढ़ा जा सकता है। 1947 का और इस प्रकार, याचिकाकर्ता, जो संबंधित प्रतिष्ठान का नियंत्रण रखता है, को न्यायनिर्णयन में भाग लेना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यदि वह संबंधित दायित्व से बचाव करना चाहता है, तो वह संबंधित दायित्व से बचाव के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकता है। इस न्यायालय ने पक्षकारों के वकीलों द्वारा उद्धृत पूर्ववर्ती कानून को भी देखा है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केवल यह कहा है कि संबंधित न्यायनिर्णयन के संबंध में पक्ष की प्रासंगिकता, आवश्यक पक्ष और/या उचित पक्ष होने के नाते, पक्ष को पक्षकार बनाने से पहले देखी जानी चाहिए। श्रम न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश को रिट क्षेत्राधिकार में चुनौती दी जा सकती है या नहीं, इस प्रश्न के संबंध में पूर्ववर्ती कानून बहुत स्पष्ट है कि यदि नियोक्ता द्वारा चुनौती दी जाती है, तो उसे बरकरार नहीं रखा जा सकता क्योंकि वह अंतिम न्यायनिर्णयन की प्रतीक्षा कर सकता है, लेकिन यदि कर्मचारी को कोई पूर्वाग्रह हो रहा है, तो वह निश्चित रूप से चुनौती दे सकता

है। उद्धृत सभी न्याय-विधियों पर विचार किया गया है। श्रम न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश, जिसमें याचिकाकर्ता को पक्षकार बनाया गया है, एक वैध आदेश है क्योंकि वर्तमान याचिकाकर्ता का प्रतिष्ठान पर नियंत्रण है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के दायित्व की सीमा का निर्धारण तभी किया जा सकता है जब उसे एक पक्ष के रूप में शामिल किया जाए।

मेसर्स अराफात पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को डीबी विशेष अपील (रिट) संख्या **1409/2019** दायर करके डिवीजन बेंच के समक्ष चुनौती दी गई थी, हालांकि उक्त विशेष अपील को 06.01.2020 को पैरा 12 और 13 में निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ खारिज कर दिया गया था:

“12. विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि त्रिपक्षीय समझौता बहुत व्यापक है और इसमें श्रमिकों के लगभग सभी अधिकार शामिल हैं। लेकिन फिर भी, यदि त्रिपक्षीय समझौते में कोई प्रतिबंध था, तो इसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 18 (3) (सी) की भावना के विपरीत नहीं पढ़ा जा सकता था। इस प्रकार, अपीलकर्ता को संबंधित प्रतिष्ठान पर नियंत्रण होने के नाते न्यायनिर्णयन में भाग लेना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यदि उसे संबंधित दायित्व से बचाव करना है, तो वह संबंधित दायित्व से अपना बचाव करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकता है। विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत और निष्पक्ष है और अपीलकर्ता के लाभ के लिए है। इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ विद्वान न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता कंपनी को संदर्भ में एक पक्ष के रूप में शामिल करके कोई गलती नहीं की है।

13. हमारा यह सुविचारित मत है कि विद्वान एकल न्यायाधीश और विद्वान न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में कोई अवैधता या त्रुटि नहीं की है। अतः, इन परिस्थितियों में, हमें इन अपीलों में कोई दम नहीं दिखता और ये खारिज किए जाने योग्य हैं।

15. विभिन्न अवसरों पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों की यह राय थी कि पक्षों के बीच कार्यवाहियों की बहुलता से बचने के लिए, न्यायालय के समक्ष लंबित वाद में तीसरे पक्ष को उचित पक्षकार के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। अमित कुमार शां बनाम फरीदा खातून के मामले में, जिसकी रिपोर्ट **2005 (11) एससीसी 403** में की गई थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि आदेश 1 नियम 10 और आदेश 22 नियम 10 सीपीसी के प्रावधानों के संयुक्त वाचन और संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा

52 के तहत निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, अचल संपत्ति में हित के लंबित हस्तांतरिती उस पक्षकार का हित-प्रतिनिधि होता है जिससे उसने ऐसा हित अर्जित किया है। वह मुकदमे या अन्य कार्यवाहियों में शामिल होने का हकदार है, जहां उसके हित-पूर्ववर्ती को मुकदमे में पक्षकार बनाया जाता है, और वह मामले के गुण-दोष के आधार पर सुनवाई का हकदार है।

अवलोकन:

16. अब वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस लौटते हुए, यह स्पष्ट है कि अपनी संपत्ति बेचने के बाद, प्रतिवादी-कंपनी ने तीसरे पक्ष के अधिकार/हित बनाकर कुल 15,50,00,000/- रुपये (पंद्रह करोड़ पचास लाख रुपये) की प्रतिफल राशि प्राप्त की है और उसके बाद, इसे दिवालिया घोषित करने के लिए एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया है। यदि एनसीएलटी प्रतिवादी-कंपनी को दिवालिया घोषित करता है और श्रम न्यायालय प्रतिवादी-कर्मचारी के पक्ष में औद्योगिक विवाद का फैसला करता है, तो पुरस्कार के अनुपालन का प्रमुख मुद्दा उठेगा, कि पुरस्कार के अनुपालन के लिए कौन उत्तरदायी और जिम्मेदार होगा आदि और इन सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में हैं और सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद श्रम न्यायालय द्वारा इसका फैसला किया जाएगा।

निष्कर्ष:

17. अतः, ऐसी परिस्थितियों में, यह उत्तर देना जल्दबाजी होगी कि याचिकाकर्ता कंपनी अपनी भूमि की खरीद के आधार पर प्रतिवादी कंपनी के मामलों के लिए उत्तरदायी है या नहीं। इस मुद्दे पर श्रम न्यायालय द्वारा सभी पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के बाद उचित समय पर निर्णय लिया जाना आवश्यक है। अतः, श्रम न्यायालय ने याचिकाकर्ता कंपनी को कार्यवाही में पक्षकार बनाकर कोई त्रुटि नहीं की है।

18. उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर, रिट याचिका में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और यह तदनुसार खारिज किए जाने योग्य है।

19. स्थगन आवेदन और सभी विविध आवेदन (यदि कोई लंबित हों) खारिज किए जाते हैं।

20. आदेश जारी करने से पूर्व, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में जो कुछ भी कहा गया है, उसे मामले के गुण-दोषों पर इस न्यायालय की अभिव्यक्ति या राय नहीं माना जाना चाहिए और यह आदेश याचिकाकर्ता-कंपनी के मामले के गुण-दोष के आधार पर किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह उत्पन्न नहीं करेगा तथा दायित्व का निर्णय श्रम न्यायालय द्वारा, सभी पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर, विधि के अनुसार किया जाएगा।

अतिरिक्त निर्देशः

21. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि औद्योगिक विवाद पिछले 24 वर्षों से पक्षों के बीच लंबित है, श्रम न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह लंबित कार्यवाही में तेजी लाए और विवाद का यथाशीघ्र, अधिमानतः इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर, शीघ्रता से निर्णय करे।

(अनूप कुमार ढांड), जे

कुडी/32

अस्वीकरणः इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी